भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4737
21अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग

†4737. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के परिणामस्वरूप कृषि, बागबानी और पुष्प-उत्पादों के मूल्य संवर्धन में वृद्धि हुई है और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा 30 जून, 2025 तक उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत और वित्तपोषित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्य संवर्धन परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उक्त योजना से देश की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और मूल्य संवर्धन परियोजनाओं ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रोत्साहन तभी स्वीकार्य हैं जब योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदित खाद्य उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण सहित विनिर्माण प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला भारत में हो। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों के कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कुल निर्यात वर्ष 2019-20 के संदर्भ में वर्ष 2024-25 तक 13.23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़ा है। यह योजना पुष्प उत्पादन को कवर नहीं करती है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा देश भर में कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 170 आवेदकों की 278 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई है। जून 2025 तक प्रोत्साहन के रूप में कुल ₹1726.60 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): इस योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में प्रति वर्ष 35.00 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लगभग 3.39 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर हेतु "वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4737 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रमांक	**राज्य**	**पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत इकाइयों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	38
2	असम	4
3	बिहार	7
4	छत्तीसगढ़	1
5	गोवा	1
6	गुजरात	32
7	हरियाणा	9
8	हिमाचल प्रदेश	4
9	जम्मू और कश्मीर	2
10	झारखंड	2
11	कर्नाटक	21
12	केरल	10
13	मध्य प्रदेश	10
14	महाराष्ट्र	41
15	ओडिशा	5
16	पंजाब	9
17	राजस्थान	6
18	तमिलनाडु	20
19	तेलंगाना	13
20	उत्तर प्रदेश	27
21	उत्तराखंड	7
22	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	278

****